



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54808

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8168 वर्ष 2026

वंश नेहरा

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष राय, ओम प्रकाश राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. श्री आर.पी. सिंह और श्री विशाल सिंह, विद्वान अधिवक्ताओं ने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से अपना अधिकार पत्र दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि उसने पीड़िता को 31.12.2024 को एक होटल/रिसॉर्ट में बहला-फुसलाकर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो बनाकर उसकी तस्वीर भी खींची, जिसे फर्जी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक और पीड़िता दोनों बालिग हैं और पीड़िता ने अपने बाद के (मजीद) बयान में इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो किसी सोशल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है और उसे आशंका थी कि ऐसा अपलोड किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज बयान की ओर दिलाया है। जिसमें उसने कहा है कि वह 16.10.2025 को एक्सएन रिजॉर्ट गई थी, जबकि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक और पीड़िता 12.10.2025 और 16.09.2025 को उसके होटल में आए थे। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक और पीड़िता के होटल में प्रवेश के संबंध में विरोधाभास है, जो स्वयं अभियोजन पक्ष की कहानी का खंडन करता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि वास्तव में आवेदक और पीड़िता बालिग हैं और उनके बीच संबंध थे, जो उनके विवाह के अनुष्ठान में सिद्ध नहीं हो सके, जिसके कारण आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। वे

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिस्थितियाँ, जिनके अनुसार अधिवक्ता ने बताया है कि जिनसे आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष पूरी निष्ठा से उपस्थित रहेगा। साथ ही, वह न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 25.12.2025 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों, साक्ष्य की प्रकृति और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। अतः जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. आवेदक वंश **नेहरा**, जो प्रकरण अपराध संख्या 434/2025 में धारा 64(1), 351(3), 123 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन मसूरी, जिला गाजियाबाद के अंतर्गत आरोपित है, को निजी मुचलके और दो स्थानीय भारी जमानतों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानत राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक को अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।
 - iv) आवेदक को उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करना चाहिए जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करना चाहिए जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय को कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

18 मार्च, 2026

एसए

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”